



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 29, 2001/भाद्र 7, 1923

No. 229]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 29, 2001/BHADRA 7, 1923

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2001

सं. टीएएमपी/12/2001-जेएनपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार रुपए मूल्य-वर्ग के वर्तमान कुछ प्रशुल्कों को अमेरिकी डॉलर मूल्य-वर्ग में परिवर्तित करने के लिए न्हावा-शेवा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (एनएसआईसीटी) के प्रस्ताव से संबंधित मामले को बंद करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/12/2001-जेएनपीटी

न्हावा-शेवा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (एनएसआईसीटी)

आवेदक

आदेश

(अगस्त, 2001 के 9वें दिन पारित किया गया)

यह मामला रुपए मूल्य-वर्ग के वर्तमान कुछ प्रशुल्कों को अमेरिकी डॉलर मूल्य-वर्ग में परिवर्तित करने के लिए न्हावा-शेवा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (एनएसआईसीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. एनएसआईसीटी का यह प्रस्ताव जनवरी, 2001 में प्रशुल्क मामले के रूप में पंजीकृत किया गया था। परंतु यह प्रस्ताव एनएसआईसीटी के प्रबंध निदेशक द्वारा किए गए मौखिक अनुरोध के कारण प्रयोक्ताओं/पत्तन-प्रयोक्ताओं की प्रतिनिधि संस्था को परिचालित नहीं किया गया था। उन्होंने सुझाव दिया था कि एनएसआईसीटी महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण कार्यालय की प्राथमिक टिप्पणियों के आधार पर अपने प्रस्ताव में संशोधन करेगा और संशोधित प्रस्ताव विचार-विमर्श के लिए रखा जा सकता है।

2.2. कुछ प्रशुल्कों को अमेरिकी डॉलर मूल्य-वर्ग में परिवर्तित करने के लिए एनएसआईसीटी के अनुरोध पर इस प्राधिकरण द्वारा पहले विचार किया गया था और 5 दिसम्बर, 1998 तथा 10 अप्रैल, 2000 को पारित अपने आदेशों में दिए गए कारणों से अस्वीकार कर दिया गया था।

2.3. एनएसआईसीटी ने वर्तमान प्रस्ताव में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया है :

- (i) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण अमेरिकी डॉलर मूल्य-वर्ग के प्रशुल्कों का अनुमोदन करने में असमर्थ क्यों है, इसका मुख्य कारण यह है कि एनएसआईसीटी प्रशुल्क में घाटशुल्क, परिवहन और रेल के ढाँचागत घटक शामिल हैं जिन्हें डॉलर मूल्य-वर्ग में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
- (ii) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ने अपने आदेश में उल्लेख किया था कि अमेरिकी डॉलर मूल्य-वर्ग के प्रशुल्कों के प्रश्न की जाँच लागत के युक्तिसंगत घटकों पर पर्याप्त सूचना प्राप्त होने पर नए सिरे से की जाएगी।
- (iii) एनएसआईसीटी ने जेएनपीटी से इन सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास किया था, परंतु जेएनपीटी विवरण देने का इच्छुक नहीं था क्योंकि वे इसे गोपनीय समझते थे।

2.4. इस परिप्रेक्ष्य में, एनएसआईसीटी ने अनुमोदित प्रशुल्कों को विभिन्न घटकों में विभक्त किया है और गैर-कार्गो न होने का दावा किए जाने वाले घटकों के डॉलर मूल्य-वर्ग का अनुकरण किया है। वर्तमान प्रशुल्कों को विभक्त करने के लिए एनएसआईसीटी ने घाटशुल्क दरों, नौभरण योजना, बौधना/खोलना प्रमारों आदि के संबंध में विभिन्न कल्पनाएँ की हैं।

3. प्रस्ताव की जाँच की गई और हमारे कार्यालय के 23 फरवरी, 2001 के पत्र द्वारा एनएसआईसीटी से स्पष्टीकरण के लिए बहुत-से मुद्दे उठाए गए। एनएसआईसीटी को इस प्राधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों/अभिमतों के आधार पर अपने प्रस्ताव को संशोधित करने और संशोधित प्रस्ताव को भेजने का सुझाव भी दिया गया था ताकि विचार-विमर्श की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके।

4.1. मै0 पी एण्ड ओ पत्तन (आई) लिमिटेड ने अपने 16 मार्च, 2001 के पत्र द्वारा 23 फरवरी, 2001 के हमारे पत्र में कही गई बातों को बेहतर समझने के लिए अधिकारी स्तर की एक बैठक करने का अनुरोध किया था। तदनुसार, मै0 पी एण्ड ओ पत्तन (आई) लिमिटेड के वितीय नियंत्रक 3 अप्रैल, 2001 को इस प्राधिकरण के अधिकारियों से मिले थे और प्रस्ताव से संबंधित युक्तिसंगत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की थी। चर्चा के दौरान, इसके प्रतिनिधि को बताया गया था कि एनएसआईसीटी नवम्बर, 2000 के संशोधन में जेएनपीटी प्रशुल्क से अलग हो गया था और जेएनपीटी प्रशुल्क का अनिवार्य रूप से बिना कोई संदर्भ लिए उसे अपनी लागतों के आधार पर मित्र-मित्र सेवा घटकों के लिए दरें तय करनी चाहिए। एनएसआईसीटी के प्रबंध निदेशक को भी जब वह 13 जून, 2001 को इस प्राधिकरण के कार्यालय में आए थे, व्यक्तिगत रूप से स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी।

4.2. चूंकि एनएसआईसीटी से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ इसलिए एनएसआईसीटी के लिए उन्हें भेजे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक समय सीमा निश्चित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, 27 जून, 2001 को पत्र भेजकर एनएसआईसीटी से अपना संशोधित प्रस्ताव अथवा इस प्राधिकरण के 23 फरवरी, 2001 के पत्र में उल्लिखित बातों पर अपनी टिप्पणियों/अभिमत दो सप्ताह के अंदर भेजने का अनुरोध किया गया। यह भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि निर्धारित समयावधि के अन्दर प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो मामला बंद कर दिया जाएगा।

4.3. इस प्राधिकरण को एनएसआईसीटी से अभी तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

5. एनएसआईसीटी से माँगी गई सूचना प्रस्ताव की आगे की जाँच से संबद्ध है। चूंकि यह प्रस्ताव एक मामले के रूप में पंजीकृत किया गया था इसलिए इसे अनिश्चितकाल के लिए लंबित रखना संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि एनएसआईसीटी के विशेष अनुरोध पर यह प्रस्ताव प्रयोक्ताओं की टिप्पणियों के लिए परिचालित नहीं किया गया था।

6. उपर्युक्त स्थिति के आलोक में और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण एनएसआईसीटी से अपेक्षित सूचना न मिलने के कारण यह मामला बंद करने का निर्णय लेता है। यदि बाद में एनएसआईसीटी से अपेक्षित सूचना अथवा संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होता है तो इस पर नए सिरे से विचार किया जाएगा।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन/143/2001/असाधारण]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th August, 2001

No. TAMP/12/2001-JNPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby closes the case relating to the proposal of the Nhava Sheva International Container Terminal Limited (NSICT) for denomination in US dollar terms of the some of its existing tariffs that are at present denominated in rupee terms as in the Order appended hereto.

SCHEDULE**Case No. TAMP/12/2001-JNPT**

**The Nhava Sheva International Container
Terminal Limited (NSICT)**

Applicant

ORDER

(Passed on this 9th day of August 2001)

This case relates to a proposal received from the Nhava Sheva International Container Terminal Limited (NSICT) for denomination in US dollar terms of the some of its existing tariffs that are at present denominated in rupee terms.

2.1. This proposal of the NSICT was registered as a tariff case in January 2001. The proposal was, however, not circulated among users / representative body of port-users because of a verbal request made by the Managing Director, NSICT. He suggested that the NSICT would revise its proposal based on the preliminary observations of the TAMP's Office; and, the revised proposal might be taken up for consultation.

2.2. The requests of the NSICT for denomination of some of its tariffs in US dollar terms were considered earlier by this Authority and disallowed for reasons given in its Orders passed on 5 December 1998 and 10 April 2000.

2.3. In the instant proposal, the NSICT has made the following points:

- (i). The principal reason why the TAMP is unable to approve US dollar denominated tariffs is that the NSICT tariff includes wharfage, transportation and rail infrastructure components which cannot be denominated in US dollar terms.
- (ii). The TAMP had stated in its Order that the question of US dollar denominated tariffs would be examined afresh on receipt of sufficient information on the relevant components of the cost.
- (iii). The NSICT attempted to obtain these information from the JNPT; but, the JNPT was unwilling to give the details as they were deemed to be confidential.

2.4. In this backdrop, the NSICT has split the approved tariffs into various components and sought dollar denomination of those components claimed to be non-cargo related. For splitting the existing tariffs, the NSICT has made various assumptions about wharfage rates, stowage planning, lashing / unlashng charges, etc.

3. The proposal was scrutinised and a number of issues were raised for clarification by the NSICT vide our Office letter dated 23 Feb. 2001. The NSICT was also advised to reformulate its proposal based on the comments / observations made by this Authority and forward a revised proposal so that the consultation process could be initiated.

4.1. M/s. P & O Ports (I) Limited vide its letter dated 16 March 2001 requested for an official level meeting for a better understanding of the points made in our letter dated 23 February 2001. Accordingly, the Financial Controller, P & O Ports (I) Limited met the officials of this Authority on 3 April 2001 and discussed the relevant issues relating to the proposal in detail. During the discussion, it was mentioned to its representative of that the NSICT had branched off from the JNPT tariff in the November 2000 revision; and, it should work out rates for the different service components based on its own costs without necessarily making any reference to the JNPT tariff. The position was also explained to the Managing Director (NSICT) personally when he visited the office of this Authority on 13 June 2001.

4.2. Since no response was received from the NSICT, it was decided to set a time limit for the NSICT to respond to the queries sent to them. Accordingly, a letter was sent on 27 June 2001 requesting them to forward its revised proposal or its comments / observations on the points mentioned in this Authority's letter dated 23 February 2001 within two weeks. It was also made very clear that if no response was received within the stipulated time limit, the case would be closed.

4.3. This Authority has not received any response from the NSICT so far.

5. The information asked for from the NSICT is relevant for further scrutiny of the proposal. Since, the proposal was registered as a case, it may not be possible to keep it pending indefinitely. It is noteworthy that the proposal has not been circulated for comments among the users, at the specific request of the NSICT.

6. In the light of the position explained above, and based on a collective application of mind, this Authority decides to close this case due to non-availability of requisite information from the NSICT. If the requisite information or a revised proposal is received subsequently from the NSICT, it will be considered afresh then.

S. SATHYAM, Chairman

[No. ADVT./143/2001/Extra.]